दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स मध्य प्रदेश

जून 2022

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोनः 8750187501
ई-मेलः online@groupdrishti.com

अनुक्रम

मध्य प्रदेश **3**

- भारत की पहली बुलेट क्रशर मशीन मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी में स्थापित 3
- राज्यसभा निर्वाचन, 2022 3
- 'यही एक पृथ्वी' विषय पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम 4
- ईट राइट चैलेंज में इंदौर को मिला पहला स्थान 4
- ग्वालियर आर्म-रेसलिंग टीम ने राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जीते 25 पदक 5
- जन-अभियान परिषद और ईशा फाउंडेशन के मध्य एमओयू 5
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मलखंब में मध्य प्रदेश बना ओवरऑल चैंपियन 6
- एसआईएसटीईसी को मिली 'NBA' मान्यता 6
- मध्य प्रदेश में मिला असामान्य टाइटेनोसॉरिड डायनासोर का अंडा 6
- डीएस ग्रुप ने मध्य प्रदेश में जल आर्थिक क्षेत्र का शुभारंभ किया 7
- वन विहार की वेबसाइट नये स्वरूप में हुई लॉन्च 8
- सिकल सेल रोग 8
- कूनो पालपुर सेंचुरी में अफ्रीकन चीतों के बाड़े के इर्द-गिर्द पर्यटन बंद रखने की सिफारिश 9
- आईडीएसपी की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में मध्य प्रदेश सम्मानित 9
- एशियन पॉवरलिफ्टिंग में राज्य के शैलेंद्र व तुषार ने जीता स्वर्ण एवं रजत पदक 10
- 27 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक बरकरार, हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में संशोधन से किया इनकार 10
- मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की दूसरी टेस्टिंग लेब को मिला एनएबीएल सर्टिफिकेट 11
- मध्य प्रदेश बना रणजी ट्रॉफी, 2022 का विजेता 11
- लक्षिका डागर बनीं मध्य प्रदेश की सबसे युवा सरपंच 12
- राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के महत्त्वपूर्ण निर्णय 12
- चुनाव मोबाइल ऐप 13
- मध्य प्रदेश में गर्भावस्था के दौरान संस्थागत जाँच और देखभाल में हुई बढ़ोतरी 13

नोट :

मध्य प्रदेश

भारत की पहली बुलेट क्रशर मशीन मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी में स्थापित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में भारत की पहली बुलेट क्रशर मशीन की स्थापना की गई। इस मशीन में इस्तेमाल किये गए कारतूस के शेल को नष्ट किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- इस मशीन के उपयोग से इस्तेमाल किये गए बुलेट को दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा। इस व्यवस्था से कारतूस का दुरुपयोग नहीं होगा।
- गौरतलब है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में शूटिंग की शॉटगन, पिस्टल और रायफल विधाओं में लगभग 100 से अधिक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक मनशेर सिंह, जसपाल राणा तथा सुमा शिरूर से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों के लिये न्यूट्रीशियन, सायकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइंस डॉक्टर, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रशिक्षक भी उपलब्ध हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में 50 मीटर फाइनल शूटिंग रेंज का कार्य प्रगति पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिये पृथक् से फाइनल शूटिंग रेंज की आवश्यकता होती है। इसके पूर्ण होने पर एशिया कप और अन्य अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा सकेंगी।

राज्यसभा निर्वाचन, 2022

चर्चा में क्यों ?

3 जून, 2022 को मध्य प्रदेश के रिटर्निंग ऑफिसर ने द्विवार्षिक निर्वाचन के लिये राज्यसभा की तीनों सीटों के प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- निर्वाचित सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी की कविता पाटीदार, सुमित्रा बाल्मिक तथा भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के विवेक कृष्ण तन्खा शामिल हैं।
- इन सदस्यों को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के तहत निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है।
- राज्यसभा के उक्त तीनों सदस्य उन तीनों सदस्यों के स्थानों को भरेंगे, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 29 जून, 2022 को निवृत्त हो रहे हैं।
- गौरतलब है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं।
- सदन में वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है।

नोट :

'यही एक पृथ्वी' विषय पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

5 जून, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 'यही एक पृथ्वी' विषय पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम से सभी ज़िले वर्चुअली जुड़े थे।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी शासकीय कार्यालयों को बिजली की खपत में 10 प्रतिशत की कमी करने के निर्देश दिये गए हैं, जिन शासकीय कार्यालयों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो सकता है, वहाँ सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
- साथ ही मुख्यमंत्री ने पर्यावरण-संरक्षण के लिये कार्यरत संस्थाओं एवं नागरिकों को सम्मानित किया और नर्मदा नदी के तट पर वृक्षारोपण की योजना संबंधित वन विभाग की पुस्तक 'नर्मदा नदी के जलग्रहण क्षेत्र का संरक्षण-वृक्षारोपण अभियान, 2022' का विमोचन भी किया गया।
- उल्लेखनीय है कि विश्व पर्यावरण दिवस को वृक्षारोपण संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरकंटक को रिज़र्व फॉरेस्ट घोषित किया जाएगा। पर्यावरण-संरक्षण की दृष्टि से संवेदनशील और नर्मदा के उद्गम-स्थल के आस-पास स्थानीय परिवेश के प्रतिकूल लगे यूकेलिप्टिस के पेड़ों के स्थान पर परिवेश के अनुरूप उपयुक्त प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री ने पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के नागरिकों को पाँच संकल्प दिलवाए, जिसमें वृक्षारोपण के लिये सक्रिय रहना, ऊर्जा संरक्षण के लिये बिजली बचाना, वाहनों का मितव्ययी उपयोग सुनिश्चित करने के लिये वाहन पूल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र के अनुरूप ट्रिपल आर अर्थात रिफ्यूज, रियूज और रिसायकल का पालन शामिल है।
- मुख्यमंत्री ने पर्यावरण-संरक्षण के लिये हरियाली अमावस्या के दिन आम जनता से प्रत्येक ग्राम, पंचायत, विकास खंड, ज़िला मुख्यालय में वृक्षारोपण करने की अपील की।
- विदित है कि प्रदेश में वृक्षारोपण के लिये आरंभ किये गए अंकुर अभियान में अब तक प्रदेशवासियों द्वारा 16 लाख 50 हज़ार पौधे लगाए गए हैं।
- इस कार्यक्रम में पर्यावरण-संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिये वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिये भोपाल रेलवे स्टेशन, हाईडलबर्ग सीमेंट दमोह, इप्का लेबोरेट्रीज रतलाम, नीलम वेल्फेयर सोसायटी शहडोल, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, इंदौर, नगर परिषद पिपलिया मंडी मंदसौर और धार के ग्राम नवादपुरा के कमल पटेल को सम्मानित किया गया।
- नर्मदा नदी के संरक्षण के लिये वन विभाग द्वारा 24 ज़िलों के 33 वन मंडलों में बिगड़े वनों को अच्छे वनों में बदलने हेतु कुल 18 हज़ार 406 हेक्टेयर क्षेत्र में एक करोड़ 32 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

ईट राइट चैलेंज में इंदौर को मिला पहला स्थान

चर्चा में क्यों ?

7 जून, 2022 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने इंदौर को ईट राइट चैलेंज (Eat Right Challenge) स्पर्द्धा का पहला पुरस्कार प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- 'ईट राइट चैलेंज फॉर सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स' के तहत खाद्य सुरक्षा की पहलों को अपनाने, नियम और परिवर्तन को बढ़ावा देने के प्रयासों को मान्यता देने के उद्देश्य से देश के 75 शहरों और ज़िलों को विजेता चुना गया है।
- इस स्पर्द्धा में देश के 188 शहरों ने अपना पंजीकरण कराया था, जिनमें से सर्वोच्च अंकों के साथ इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
- इसके साथ ही प्रदेश के 7 अन्य ज़िलों- भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और सतना को भी ईट राइट चैलेंज फॉर सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स के तहत खाद्य सुरक्षा को लेकर सकारात्मक परिर्वतन के लिये सम्मानित किया गया।

नोट :

- भोपाल, उज्जैन, जबलपुर ने क्रमश: 3, 5 और 7वाँ स्थान प्राप्त किया है। ग्वालियर को 12वाँ, रीवा को 17वाँ, सागर को 23वाँ और सतना को 74वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की 4 स्मार्ट सिटी- इंदौर, जबलपुर, सागर और उज्जैन को ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज में शीर्ष 11 स्मार्ट सिटीज में स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया।
- ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज के तहत घरेलू स्तर पर रिसाइक्लिंग और अतिशेष भोजन दान करने की नीति के लिये इंदौर स्मार्ट सिटी को पुरस्कृत किया गया।
- जबलपुर स्मार्ट सिटी को बच्चों में मोटापे की समस्या से निपटने के लिये कार्टून किरदारों द्वारा व्यवहार परिवर्तन को लेकर शुरू की गई पहल के लिये सम्मानित किया गया।
- सागर स्मार्ट सिटी द्वारा बच्चों को खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण देने के लिये वीडियो गेम और युवा पोषण एंबेसेडर तैयार करने के लिये पुरस्कृत किया गया, जबकि हाइड्रोपोनिक्स को बढ़ावा देने के लिये उज्जैन स्मार्ट सिटी को पुरस्कृत किया गया।

ग्वालियर आर्म-रेसलिंग टीम ने राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जीते 25 पदक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ग्वालियर आर्म-रेसलिंग टीम ने हैदराबाद में आयोजित 44वीं राष्ट्रीय आर्म-रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 पदक जीते।

प्रमुख बिंदु

- 44वीं राष्ट्रीय आर्म-रेसलिंग चैंपियनशिप 31 मई से 6 जून, 2022 तक हैदराबाद के गाचीबोवली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में 25 राज्यों के 900 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया।
- मध्य प्रदेश ने चैंपियनशिप में केरल के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। ग्वालियर की टीम ने चैंपियनशिप में 25 पदक जीतकर अपना 44 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है।
- ग्वालियर आर्म-रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष केशव पांडे ने बताया कि विक्रम पुरस्कार विजेता मनीष कुमार; विश्व रजत पदक विजेता अरविंद रजक; निरंजन गूर्जर; राजेंद्र महोरे; सचिन गोयल; सुजीत महोरे; उमेश पाल; योगेंद्र यादव; पूजा भदौरिया; आयुष कौशल और शिवम गूर्जर ने स्वर्ण पदक जीते। साथ ही, इनमें से कुछ ने रजत और कांस्य पदक भी जीते।
- केशव पांडे ने बताया कि ग्वालियर आर्म-रेसलिंग अकादमी आर्म-रेसलिंग के लिये देश की पहली पूर्ण अकादमी है।

जन-अभियान परिषद और ईशा फाउंडेशन के मध्य एमओयू

चर्चा में क्यों ?

10 जून, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सद्गुरु वासुदेव जग्गी की उपस्थिति में मिट्टी को बचाने के लिये राज्य सरकार और ईशा फाउंडेशन के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर हुए।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सद्गुरु वासुदेव जग्गी के मिट्टी बचाने के संदेश को प्रदेश के प्रत्येक गाँव और विकासखंड तक ले जाया जाएगा। राज्य सरकार इस दिशा में ईशा फाउंडेशन के साथ मिलकर कार्य करेगी।
- मिट्टी बचाने के लिये मध्य प्रदेश जन-अभियान परिषद द्वारा सेव स्वाईल अभियान में जन-जागरण गतिविधियाँ चलाई जाएंगी। मिट्टी बचाने के लिये राज्य शासन और ईशा फाउंडेशन द्वारा जो रोडमैप बनाया जाएगा, उसे जन-अभियान परिषद और ईशा फाउंडेशन मिलकर क्रियान्वित करेंगी।

नोट :

खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मलखंब में मध्य प्रदेश बना ओवरऑल चैंपियन

चर्चा में क्यों ?

12 जून, 2022 को मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2022 में मलखंब खेल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 पदक अपने नाम किये। इसके साथ ही मध्य प्रदेश मलखंब में ओवरआल चैंपियन बन गया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार मलखंब को शामिल किया गया है और पहली ही बार में मध्य प्रदेश चैंपियन बना है। मलखंब में मध्य प्रदेश ने 5 स्वर्ण पदक समेत कुल 12 पदक जीते।
- उज्जैन के खाचरौद के 18 साल के युवा खिलाड़ी पंकज गर्गमा ने 5 में से 3 स्वर्ण अपने नाम किये। वे प्रदेश के पहले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने खेलो इंडिया में एक दिन में तीन स्वर्ण जीते हैं। पंकज ने पोल, रोप और ओवरऑल, तीनों में 10 में से 9.10 अंक हासिल किये।
- पोल मलखंब के फाइनल में मध्य प्रदेश की हर्षिता कणडकर ने स्वर्ण तथा सिद्धि गुप्ता ने रजत पदक जीता। रोप मलखंब में हर्षिता, छत्तीसगढ़ की सरिता पायम के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं।
- लड़कों के पोल मलखंब में इंद्रजीत नागर और प्रणव कोरी संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ के मोनू नेताम के साथ दूसरे स्थान पर रहे। रोप मलखंब में पंकज गर्गमा ने शीर्ष स्थान हासिल किया, उसके बाद नागर दूसरे स्थान पर रहे। हैंगिंग मलखंब में भी गर्गमा ने शीर्ष पर रहते हुए स्वर्ण पदक जीता।
- गौरतलब है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 जून से 13 जून, 2022 तक पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम समेत चंडीगढ़, दिल्ली, शाहाबाद और अंबाला में आयोजित किये जा रहे हैं।

एसआईएसटीईसी को मिली 'NBA' मान्यता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) ने सागर समूह के भोपाल स्थित सागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (SISTec) को अपनी मान्यता प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- एसआईएसटीईसी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग और इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है।
- एनबीए पीयर टीम ने SISTec का दौरा किया और कई मापदंडों पर कॉलेज का कड़ाई से मूल्यांकन किया। दौरे के दौरान टीम ने कॉलेज में अपनाई गई ईमानदारी, बुनियादी ढाँचे, प्रबंधन, संकाय, छात्र योगदान, शिक्षण-सीखने की प्रक्रिया, संस्थागत मूल्यों और सर्वोत्तम प्रथाओं की सराहना की।
- एनबीए, भारत की स्थापना SISTec द्वारा नई प्रक्रियाओं, मानकों और मानदंडों के साथ तकनीकी शिक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देने हेतु शैक्षिक संस्थान द्वारा पेश किये गए कार्यक्रमों की गुणात्मक क्षमता का आकलन करने के लिये की गई है।

मध्य प्रदेश में मिला असामान्य टाइटेनोसॉरिड डायनासोर का अंडा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश के धार ज़िले के बाग इलाके में पहली बार भारतीय शोधकर्त्ताओं की एक टीम ने अंडे के भीतर अंडे (egg-in-egg) या असामान्य टाइटेनोसॉरिड डायनासोर अंडे (abnormal Titanosaurid dinosaur egg) की खोज की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस खोज को नेचर ग्रुप जर्नल-साइंटिफिक रिपोर्ट्स के नवीनतम अंक में प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन का शीर्षक है- 'फर्स्ट ओवम-इन-ओवो पैथोलॉजिकल टाइटेनोसॉरिड एग थ्रोस लाइट ऑन द रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ सॉरोपॉड डायनासोर' (First ovum-in-ovo pathological titanosaurid egg throws light on the reproductive biology of sauropod dinosaurs)।
- शोधकर्त्ताओं ने हाल ही में बाग शहर के निकट पड़लिया गाँव के पास बड़ी संख्या में टाइटेनोसॉरिड सॉरोपॉड घोंसलों का दस्तावेज़ीकरण किया था। इन घोंसलों का अध्ययन करते हुए शोधकर्त्ताओं ने एक असामान्य डायनासोर के अंडे सहित 10 अंडों से युक्त एक सॉरोपॉड डायनासोर के घोंसले की खोज की है।
- असामान्य अंडे में दो निरंतर और गोलाकार अंडे के खोल की परतें हैं, जो एक विस्तृत अंतराल से अलग होती हैं, जो ओवम-इन-ओवो (दूसरे अंडे के अंदर एक अंडा) पक्षियों की विकृति की याद दिलाती हैं।
- एक ही घोंसले में पैथोलॉजिकल अंडे और आसन्न अंडे की सूक्ष्म संरचना इसकी पहचान टाइटेनोसॉरिड सॉरोपॉड डायनासोर से करती है।
- यह भारत में पहली अंडे-में-अंडे की असामान्य जीवाश्म अंडे की खोज है। इससे पहले भारत में कभी भी डायनासोर, छिपकली, कछुए और मगरमच्छ सहित अन्य सरीसृपों के अंडे-में-अंडे का असामान्य जीवाश्म अंडा नहीं पाया गया है।
- इस क्षेत्र में प्रमुख लेखक डॉ. हर्ष धीमान (भूविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय) द्वारा पीएचडी फील्डवर्क के दौरान पैथोलॉजिकल अंडे की खोज की गई थी। धीमान के अलावा, टीम में विशाल वर्मा (हायर सेकेंडरी स्कूल, बकानेर, धार ज़िला) और संबंधित लेखक प्रो. गुंटुपल्ली वी.आर. प्रसाद (भूविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय) शामिल थे।
- डॉ. हर्ष धीमान ने कहा कि टाइटेनोसॉरिड घोंसले से ओवम-इन-ओवो अंडे की खोज इस संभावना को खोलती है कि सॉरोपॉड डायनासोर में मगरमच्छ या पक्षियों के समान एक डिंबवाहिनी आकारिकी थी और वे पक्षियों की अंडे देने वाली विशेषता के एक तरीके के लिये अनुकूलित हो सकते थे।
- प्रो. गुंटुपल्ली वी.आर. प्रसाद ने कहा कि यह खोज इस बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी सामने लाती है कि क्या डायनासोर के पास कछुओं और छिपकलियों या उनके निकटतम मगरमच्छों और पक्षियों के समान प्रजनन जीव विज्ञान था।
- पहले यह सुझाव दिया गया था कि मगरमच्छों और पक्षियों के खंडित प्रजननपथ के विपरीत डायनासोर का प्रजनन कार्य कछुओं और अन्य सरीसृपों (अखंडित डिंबवाहिनी-unsegmented oviduct) के समान होता है।
- मगरमच्छ हालाँकि कछुओं और अन्य सरीसृपों की तरह सभी अंडों को एक साथ ओव्यूलेट करते और छोड़ते हैं, पक्षियों के अनुक्रमिक ओव्यूलेशन के विपरीत, जो एक बार में एक अंडा देते हैं।
- नई खोज से पता चलता है कि मध्य और पश्चिमी भारत में डायनासोर के जीवाश्मों के लिये काफी संभावनाएँ हैं, जो डायनासोर प्रजातियों की विविधता और उनके घोंसले के व्यवहार एवं प्रजनन जीव विज्ञान पर महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

डीएस ग्रुप ने मध्य प्रदेश में जल आर्थिक क्षेत्र का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में डीएस (धर्मपाल सत्यपाल) समूह ने मध्य प्रदेश के खंडवा और बैतूल ज़िलों में दूसरा 'जल आर्थिक क्षेत्र' (एक एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना) लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- डीएस समूह ने उदयपुर में अलसीगढ़ और कुराबाद वाटरशेड क्षेत्रों में पहला कार्यक्रम (जल आर्थिक क्षेत्र) सफलतापूर्वक लागू करने के बाद मध्य प्रदेश में यह विकास परियोजना लॉन्च की है।
- प्रस्तावित हस्तक्षेप खंडवा ज़िले के छैगाँव माखन ब्लॉक में बरुद ग्राम पंचायत के 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में और बैतूल ज़िले के एथनेर ब्लॉक में दाभोना ग्राम पंचायत के 2400 हेक्टेयर क्षेत्र में लागू किया जाएगा।

नोट :

- कंपनी ने इन दो ज़िलों में परियोजना के कार्यान्वयन के लिये ज़मीनी स्तर के संगठनों- अर्पण सेवा संस्थान और हरितिका के साथ भागीदारी की है।
- एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजनाओं के माध्यम से 'जल आर्थिक क्षेत्र का निर्माण', अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिये प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से पानी और मिट्टी को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- इन परियोजनाओं में रिचार्ज़िंग और भंडारण संरचनाओं का निर्माण, मौज़ूदा निष्क्रिय या कम उपयोग किये गए जल निकायों का नवीनीकरण, मृदा संरक्षण उपाय, कुशल सिंचाई प्रथाओं की शुरुआत और दीर्घकालिक स्थिरता के लिये संस्थानों का निर्माण शामिल है।
- वाटरशेड संरचनाओं के कारण सतह और उप-सतह स्तर पर पानी की उपलब्धता कई गुना बढ़ जाती है, जिससे सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होती है और फसल उत्पादकता में सुधार होता है, जिसके परिणामस्वरूप हस्तक्षेप क्षेत्रों में समुदायों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है।
- यह परियोजना जलवायु के अनुकूल फसलों की कटाई के साथ-साथ ड्रिप सिंचाई और रेन गन जैसी बेहतर सिंचाई पद्धतियों के माध्यम से पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देती है।
- दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये, कंपनी स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाती है और जल उपयोगकर्त्ता समूहों, किसानों के समूह या किसी अन्य उपयुक्त सामुदायिक संस्थानों जैसे संस्थानों का निर्माण करती है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 1929 में स्थापित डीएस समूह एक बहु-व्यवसाय निगम है और मज़बूत भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ अग्रणी एफएमसीजी (फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स) समूहों में से एक है।

वन विहार की वेबसाइट नये स्वरूप में हुई लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

18 जून, 2022 को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर की नई पुन: डिजाइन और पुनर्विकसित वेबसाइट: www.vanviharnationalpark.org लॉन्च की गई है। इस नई वेबसाइट को वन विहार में नवीनतम घटनाओं, समाचारों और जनता को अद्यतन/अपडेटेड रखने के लिये डिजाइन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- आधुनिक समय के साथ तालमेल बिठाते हुए वेबसाइट में एक आधुनिक रेस्पॉन्सिव कोडिंग और डिजाइन है। वेबसाइट को, जिस भी डिवाइस पर ओपन किया जाएगा, यह वेबसाइट उस डिवाइस की स्क्रीन के आकार में स्वयं को स्वत: समायोजित कर लेगी।
- वन विहार के सभी सोशल मीडिया पेजों को भी नई वेबसाइट से जोड़ा गया है। आमजन वन विहार के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्वीटर प्रोफाइल को वेबसाइट से ही देख सकते हैं।
- वेबसाइट लगभग दैनिक आधार पर अपडेट की जाएगी और जनता अपलोड के कुछ ही मिनटों में इसे देख सकेगी। नवीनतम जानकारी को अद्यतन करने के लिये लगभग शून्य मिनट प्रतीक्षा अवधि रहेगी।
- वन विहार से संबंधित नवीनतम समाचारों को होम पेज पर एक समूह के रूप में संकलित और प्रदर्शित किया जाएगा और साथ ही प्रत्येक समाचार के लिये अलग-अलग विस्तृत पेज भी होगा।
- नवीनतम और महत्त्वपूर्ण दस्तावेज जैसे ब्रोशर आदि जनता के लिये डाउनलोड के लिये उपलब्ध होंगे। गैलरी अनुभाग को नवीनतम तस्वीरों के साथ नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।

सिकल सेल रोग

चर्चा में क्यों ?

19 जून, 2022 को विश्व सिकल सेल एनीमिया जागरूकता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग एंड मेन्यूफेक्चिरिंग (ट्रिपल आईटीडीएम) में सिकल सेल रोग के समग्र प्रबंधन पर आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यशाला का आयोजन आईसीएमआर, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया गया है।
- गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल 14 ज़िलों में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और बचाव के लिये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य, विवाह और पुनर्वास सहायता आदि पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
- सिकल सेल रोग (एससीडी) रक्त संबंधी आनुवंशिक विकार है, जो भारत के झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी ओडिशा, पूर्वी गुजरात और उत्तरी तमिलनाडु तथा केरल आदि राज्यों/क्षेत्रों में वितरित कई जनजातीय समूहों में बहुतायत में पाई जाती है।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग और समय पर प्रबंधन को मज़बूत करने के लिये उन्मुक्त परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

कूनो पालपुर सेंचुरी में अफ्रीकन चीतों के बाड़े के इर्द-गिर्द पर्यटन बंद रखने की सिफारिश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में साउथ अफ्रीका और नामीबिया से कूनो पालपुर सेंचुरी में चीतों की बसाहट की तैयारियाँ देखने आए एक्सपर्ट और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी एस.पी. यादव ने चीतों के बाड़े के इर्द-गिर्द पर्यटन गतिविधियों को पूरी तरह से बंद रखने की सिफारिश की है।

प्रमुख बिंदु

- एक्सपर्ट का कहना है कि कूनो में चीतों को जिस 5 वर्ग किमी. के एनक्लोजर में रखा जाएगा, उसके इर्द-गिर्द न तो पर्यटकों को एंट्री दी जाए और न ही इसके लिये किसी तरह के पर्यटन प्रस्ताव को मंज़ूरी दी जाए।
- इतना ही नहीं एक्सपर्ट ने चीतों के लिये बनाए गए बाड़े की फेंसिंग को ग्रीन मैट से कवर करने की भी सिफारिश की है। अफ्रीकन एक्सपर्ट ने कहा कि यदि ग्रीन मैट नहीं लगाई गई तो वे फेंसिंग को पार करने की कोशिश करेंगे। इसलिये उन्हें ग्रीन मैट लगाकर यह अहसास कराया जाएगा कि फेंसिंग के बाद कुछ नहीं है।
- चीतों के बाड़े में रहने तक फिलहाल टूरिज़्म गतिविधियों पर रोक लगाने की सिफारिश की जा रही है। इस प्रस्ताव के बाद प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की पर्यटन को बढ़ावा देने वाली कोशिशों को झटका लगा है।
- गौरतलब है कि मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग चीतों के आगमन के बाद कूनो में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये तैयारियाँ कर रहा था। इसके तहत कूनो सेंचुरी का टूरिज़्म प्लान तैयार किया गया था। इसमें प्रतिदिन पर्यटकों के अधिकतम 100 वाहनों को एंट्री देने की बात कही गई थी।
- अफ्रीका से आने वाले चीतों का कूनो अभयारण्य में अगस्त, 2022 तक आने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश विगत 27 सालों से कूनो में चीतों की बसाहट के लिये प्रयास कर रहा है। आज़ादी के 70 साल बाद इस विलुप्त जीव को एक बार फिर से देश में स्थापित कराने का प्रयास किया जा रहा है।

आईडीएसपी की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में मध्य प्रदेश सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

21 जून, 2022 को एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) और इसके अंतर्गत संक्रामक बीमारियों के विषय में तत्काल सूचना प्राप्त कर नियंत्रण और रोकथाम के उद्देश्य से आईएचआईपी (इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म) में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- नई दिल्ली में हुई आईडीएसपी की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आईडीएसपी के उप-संचालक डॉ. योगेश कौरव और डॉ. एम.पी.एस. चौहान को सम्मान-पत्र प्रदान किया।
- गौरतलब है कि आईएचआईपी कार्यक्रम में पहले ही चरण में 1 अक्टूबर, 2021 को पूरी तरह पेपरलेस के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है।
- बैठक में आईएचआईपी संयुक्त संचालक डॉ. हिमांशु चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश पहले चरण में आईडीएसपी के अंतर्गत संक्रामक बीमारियों की पहचान, बचाव और रोकथाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी को आईएचआईपी में पेपरलेस करने में सफल हुआ है।
- उन्होंने अन्य राज्यों से भी आईएचआईपी में पेपरलेस बनने हेतु मध्य प्रदेश का अनुसरण करने को कहा।

एशियन पॉवरलिफ्टिंग में राज्य के शैलेंद्र व तुषार ने जीता स्वर्ण एवं रजत पदक

चर्चा में क्यों ?

17 से 21 जून, 2022 तक कोयंबटूर में आयोजित सीनियर एशियन पॉवरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में भोपाल के पॉवरलिफ्टर शैलेंद्र सेवतिया और तुषार कदम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को स्वर्ण और रजत पदक दिलाया।

प्रमुख बिंदु

- प्रतियोगिता के 74 किग्रा. भार वर्ग में शैलेंद्र सेवतिया ने स्क्वाट स्पर्धा में 280 किग्रा., बेंचप्रेस में 185 किग्रा. और डेडलिफ्ट में 275 किग्रा., इस प्रकार कुल 740 किग्रा. भार उठाकर देश को स्वर्ण पदक दिलाया।
- इसी प्रकार प्रतियोगिता के 66 किग्रा. भार वर्ग में भोपाल के पॉवर लिफ्टर तुषार कदम ने स्क्वाट मं 240 किग्रा., बेंचप्रेस में 155 किग्रा. और डेडस्किट स्पर्धा में 230 किग्रा., इस तरह कुल 625 किग्रा. वज़न उठाकर देश को रजत पदक दिलाया।

27 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक बरकरार, हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में संशोधन से किया इनकार

चर्चा में क्यों ?

23 जून, 2022 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीएससी (लोक सेवा आयोग) में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर लगी अंतरिम रोक के आदेश में संशोधन से इनकार कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- ओबीसी आरक्षण के संबंध में दायर सभी याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस ए.के. शर्मा की युगल पीठ द्वारा की गई।
- गौरतलब है कि आशिता दूबे सहित अन्य की तरफ से प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने के खिलाफ तथा पक्ष में लगभग 60 से अधिक याचिकाएँ दायर की गई थीं। हाईकोर्ट ने कई लंबित याचिकाओं पर ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत दिये जाने पर रोक लगा दी थी।
- सरकार द्वारा स्थगन आदेश वापस लेने के लिये आवेदन दायर किया गया था। हाईकोर्ट ने 1 सितंबर, 2021 को स्थगन आदेश वापस लेने से इनकार करते हुए संबंधित याचिकाओं को अंतिम सुनवाई के निर्देश जारी किये थे।
- प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने महाधिवक्ता द्वारा 25 अगस्त, 2021 को दिये अभिमत के आधार पर पीजी नीट 2019-20, पीएससी के माध्यम से होने वाली मेडिकल अधिकारियों की नियुक्ति तथा शिक्षक भर्ती छोड़कर अन्य विभाग में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के आदेश जारी कर दिये थे। उक्त आदेश के खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
- आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने साल 1993 में इंदिरा साहनी तथा साल 2021 में मराठा आरक्षण के मामले में स्पष्ट आदेश दिये हैं कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने पर आरक्षण की सीमा 63 प्रतिशत तक पहुँच जाएगी।

नोट :

- याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से दायर जवाब में कहा गया था कि साल 2011 की जगगणना के अनुसार प्रदेश में ओबीसी वर्ग की संख्या लगभग 51 प्रतिशत है। सुनवाई के दौरान पीठ से आग्रह किया गया था कि पीएससी में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में जारी अंतरिम रोक के आदेश को संशोधित किया जाए। पीठ ने आग्रह को अस्वीकार करते हुए उक्त आदेश जारी किये।

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की दूसरी टेस्टिंग लेब को मिला एनएबीएल सर्टिफिकेट

चर्चा में क्यों ?

24 जून, 2022 को मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (मप्रपक्षेविविकं) की दूसरी टेस्टिंग लेब को नेशनल एक्रिडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) ने मान्यता प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- मप्रपक्षेविविकं की उज्जैन स्थित रीजनल मीटर टेस्टिंग की अत्याधुनिक लेब को एनएबीएल का सर्टिफिकेट मिला है।
- मप्रपक्षेविविकं इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि इससे पहले इंदौर पोलोग्राउंड स्थित ट्रांसफार्मर, केबल, कंडक्टर की टेस्टिंग करने वाली लेब को भी पिछले वर्ष एनएबीएल का सर्टिफिकेट मिला था।
- इंदौर और उज्जैन की दोनों लेब में बिजली के महत्त्वपूर्ण उपकरणों की अत्याधुनिक तरीके से टेस्टिंग हो रही है। दोनों ही लेबों को आत्मनिर्भर भारत अभियान में निर्मित किया गया।
- इसके अलावा इंदौर के पोलोग्राउंड स्थित मीटर टेस्टिंग की अत्याधुनिक लेब को भी एनएबीएल का दर्ज़ा दिलाने की सभी कार्रवाई पूर्ण कर दी गई है। दो सप्ताह में इंदौर के मीटर टेस्टिंग लेब को भी एनएबीएल का सर्टिफिकेट मिलने की पूरी संभावना है।
- गौरतलब है कि एनएबीएल भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक संघटक बोर्ड है, जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है।
- एनएबीएल देश की परीक्षण प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता देने वाली एकमात्र संस्था है।

मध्य प्रदेश बना रणजी ट्रॉफी, 2022 का विजेता

चर्चा में क्यों ?

26 जून, 2022 को मध्य प्रदेश ने बंगलुरू के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में मुंबई को छह विकेट से हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश ने पिछली बार रणजी ट्रॉफी का फाइनल वर्ष 1988-1989 में बंगलुरू के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही खेला था।
- फाइनल मुकाबले की पहली पारी में 116 और दूसरी पारी में 30 रन बनाने के लिये मध्य प्रदेश के शुभम शर्मा को फाइनल मुकाबले में 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया, जबकि पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक 982 रन बनाने वाले मुंबई के सरफराज खान को 'मैन ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया।
- रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश की टीम के कप्तान आदित्य श्रीवास्तव थे, जो इस जीत के साथ ही रणजी ट्रॉफी जीतने वाले मध्य प्रदेश के पहले कप्तान बन गए।
- वहीं चंद्रकांत पंडित मध्य प्रदेश के कोच हैं, जिन्होंने 1988-1989 में मध्य प्रदेश का रणजी ट्रॉफी में नेतृत्व किया था। उनका कोच के रूप में यह छठा रणजी खिताब है।

नोट :

लक्षिका डागर बनीं मध्य प्रदेश की सबसे युवा सरपंच

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश में संपन्न हुई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उज्जैन की 21 वर्षीय लक्षिका डागर शानदार जीत हासिल कर मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच (एक गाँव की मुखिया) बन गई हैं।

प्रमुख बिंदु

- 21 साल की लक्षिता डागर ने उज्जैन ज़िले की चिंतामन जवासिया ग्राम पंचायत से चुनाव जीतकर यह गौरव हासिल किया है।
- लक्षिका ने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को 487 मतों से हराकर यह जीत हासिल की है।
- लक्षिका ने जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के पश्चात् उज्जैन में रेडियो जॉकी तथा न्यूज़ एंकर के रूप में काम किया है।
- गौरतलब है कि ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया।
- उन राज्यों को छोड़कर, जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है ग्राम, मध्यवर्ती (प्रखंड/तालुक/मंडल) और ज़िला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई है (अनुच्छेद 243B)।
- सभी स्तरों पर सीटों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाना है [अनुच्छेद 243C(2)]
- मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिये प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग होंगे (अनुच्छेद 243K)।

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

28 जून, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में दो नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की सैद्धांतिक स्वीकृति के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं आगामी वित्तीय वर्षों के लिये मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद हेतु निर्धारित वार्षिक सीमा 150 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए करने का अनुमोदन किया गया।
- मंत्रिपरिषद ने विधायक निधि अंतर्गत विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (पूंजीगत) को 1 करोड़ 85 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ 50 लाख रुपए तथा विधायक स्वेच्छानुदान योजना में 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का निर्णय लिया।
- मंत्रिपरिषद ने ज़िला सीहोर स्थित बुदनी तहसील में 100 एम.बी.बी.एस. सीट प्रवेश क्षमता का चिकित्सा महाविद्यालय तथा 500 बिस्तर संबद्ध अस्पताल स्थापित करने के साथ नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिये 60 सीट प्रवेश क्षमता का नर्सिंग महाविद्यालय तथा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिये 60 सीट प्रवेश क्षमता का पैरामेडिकल महाविद्यालय स्थापित करने की सैद्धांतिक सहमति दी।
- इसी प्रकार उज्जैन में नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिये स्नातक पाठ्यक्रम की 100 सीटों में वृद्धि करने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान की।
- मंत्रिपरिषद ने मुरैना में रूरल टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने को मंज़ूरी दी।
- मंत्रिपरिषद ने जबलपुर ज़िले की छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना, लागत राशि 434 करोड़ 21 लाख रुपए सैंच्य क्षेत्र 16 हज़ार 875 हेक्टेयर और कुण्डालिया बहुउद्देशीय वृहत् सिंचाई परियोजना ज़िला राजगढ़ लागत राशि 4614 करोड़ 73 लाख रुपए सैंच्य क्षेत्र 1 लाख 39 हज़ार 600 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी।
- मंत्रिपरिषद द्वारा कुण्डू टास्कफोर्स समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की तर्ज़ पर राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन का निर्णय लिया गया। प्रदेश में सांख्यिकी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिये अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने के लिये कुण्डू टास्कफोर्स गठित की गई थी। आयोग के अध्यक्ष प्रख्यात सांख्यिकी विशेषज्ञ होंगे, जिन्हें इस क्षेत्र में 20 वर्ष का अनुभव होगा। आयोग में 1 सदस्य राज्य सरकार नामित करेगी और अधिकतम 6 सदस्य विषय-विशेषज्ञ के रूप में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

नोट :

चुनाव मोबाइल ऐप

चर्चा में क्यों ?

29 जून, 2022 को मध्य प्रदेश नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष-2022 के लिये मतदाता एवं अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु 'चुनाव' मोबाइल ऐप (एंड्राइड आधारित) को अद्यतन (updation) किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस ऐप के माध्यम से चुनाव संबंधी जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।
- राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने जानकारी दी कि 'चुनाव' ऐप में मतदाता की जानकारी, महापौर, पार्षद, ज़िला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य पद के अभ्यर्थी की जानकारी मय शपथ-पत्र के सार-पत्र अनुसार उपलब्ध है।
- इस ऐप में महापौर, पार्षद, ज़िला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम भी मिलेंगे।

मध्य प्रदेश में गर्भावस्था के दौरान संस्थागत जाँच और देखभाल में हुई बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4 (2015) और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 (2020-21) के तुलनात्मक आँकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य संस्थाओं में जाँच और देखभाल करवाने वाली गर्भवती माताओं की संख्या में पिछले 5 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज़ की गई है।

प्रमुख बिंदु

- नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के प्रतिवेदन में बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं में से 75 प्रतिशत ऐसी महिलाएँ हैं, जिनकी गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास में स्वास्थ्य संस्था पर जाँच और देखभाल की गई। वर्ष 2015 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4 में ऐसी महिलाओं की संख्या 53 प्रतिशत थी।
- सर्वे-5 के प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि गर्भवती माताओं में से आधे-से-अधिक (58 प्रतिशत) ने प्रसव के पहले 4 अथवा 4 से अधिक बार स्वास्थ्य संस्थाओं में जाँच और देखभाल की सुविधा प्राप्त की। ऐसा करने वाली शहरी महिलाओं की संख्या ग्रामीण महिलाओं की तुलना में अधिक रही।
- मध्य प्रदेश में 91 प्रतिशत प्रसव स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ हुए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4 की तुलना में हेल्थ सर्वे-5 में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ हुए प्रसवों में वृद्धि 81 प्रतिशत से बढ़कर 91 प्रतिशत हुई है।
- उल्लेखनीय है कि मई 2022 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 की रिपोर्ट जारी की गई।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey–NFHS) बड़े पैमाने पर किया जाने वाला एक बहुस्तरीय सर्वेक्षण है, जो पूरे भारत में परिवारों के प्रतिनिधि नमूने के रूप में किया जाता है।

नोट :